(b) whether it is a fact that Officers on Special Duty have been sent to foreign countries to meet with companies and attract them to India;

(c) whether such offices have requested gaint multinationals like Philip Morris to invest in India;

(d) the number of new jobs that will be created by Philip Morris in India within the next five years; and

(e) if so, the details of such proposals and the keenness of Government to attract them?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) The main functions of Foreign Investment Promotion Board *inter-alia* include expeditious clearance of FDI proposals, periodic review of approved projects, review of general and sectoral policy issues and investment promotion activities. The Ministry of Industry holds "Destination India" events abroad to promote FDI in the country. The event addresses prospective investors in general without company specific focus.

(d) and (e) Government has received a proposal from M/s. FTR Holdings, a subsidiary of Philip Morris for setting up a 100% subsidiary with an investment of Rs. 320 crore to set up international standard tobacco research and technical services centre, agro based infrastructure, to sell cut tobacco products in bulk to licensed manufacturers of cigarettes and provide marketing advertising and distribution support to licensed manufacturers of cigarettes, bulk processing in the tobacco growing regions of Southern India etc. As per application of the company, the project will generate direct employment opportunities to 250 personnel.

The proposal will be considered by the Government as per existing policy and based on the recommendations of the concerned Administrative Ministries.

भवन निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया जाना

2072. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने भवन निर्माण को उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कांउसिल ने यह भी सिफारिश की है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक की मकान निर्माण परियोजनाओं को सी०आई०डी०सी० के पास पंजीकृत करवाया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) भवन निर्माण को उद्योग का दर्जा देने के बारे में बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया से कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) हमें 10 करोड़ रुपये से अधिक मकान निर्माण परियोजना के बारे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए सी०आई०डी०सी० में पंजीकरण आवश्यक है।

Allocation of funds for the North Eastern States

2073. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the amount of funds allotted in the Ninth Five Year Plan for the North-Eastern States for development of Industries on State-wise basis;

(b) the measures being contemplated by Government for revitalisation of the State Industrial Corporation in the North-Eastern States; and

(c) whether Government have given one-time financial measure to revive them?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) For the Central Sector, the allocation of

funds is made Ministry/Department-wise and not State-wise. The Ninth Five Year Plan outlays for the North Eastern States pertaining to large and medium, village and small scale industries (VSI) and mineral sectors are given below:

(Rs. In lakhs)

States	VSI	Large & Medium Industry	Minerals	Total
Arunachal Pradesh	3432	806	372	4610
Assam	17477	19500	1027	38004
Meghalaya	3200	5800	1200	10200
Mizoram	5973	534	385	6892
Nagaland	8528	1674	1900	12102
Manipur	4284	8227	140	12651
Tripura	3799	4120	15	7934
North Eastern Council	—	1617	183	1800

(b) and (c) The new industrial policy for the North East provides for restructuring of state Public Sector Undertakings in the North Eastern States from the National Renewal Fund (NRF). Based on the NRF guidelines, the State Government of the North East have been requested to indicate the requirement of funds under NRF assistance.

अनिवासी भारतीयों/घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा निवेश

2074. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 1998 से 31 जनवरी, 1999 के बीच देश के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी अनिवासी भारतीयों और घरेलू निजी क्षेत्रों से निवेश में काफी अधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्यात्मक कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि में देश में राज्य-वार कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया और 1997-98 की तुलना में यह निवेश कितना है;

(घ) क्या सरकार ने पूंजी निवेश में कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) इस कमी के कारण देश के औद्योगिक विकास को कितनी हानि हुई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह (जी०डी०आर० को छोड़कर) 1997 (जनवरी-दिसम्बर) में 12,989 करोड़ रुपये की तुलना में 1998 .(जनवरी-दिसम्बर) के दौरान 13,265 करोड़ रुपये था। इसमें अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी निगमित निकायों द्वारा किया गया निवेश शामिल है। घरेलू निवेश के मामले में अप्रैल, 1998-जनवरी, 1999 के दौरान अखिल भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा दी गई स्वीकृति एवं किए गए वितरण दोनों ही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 32.6% तथा 14.5% वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे मासिक एस०आई०ए० सांख्यिकी में उपलब्ध होते हैं, जिसका संसद पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है।

Permissible component of expenditure under PMRY

2075. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the permissible component of expenditure under PMRY on plant and machinery, other consumables, labour charges (wages), miscellaneous expenses etc. under different sectors; and